सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 98 | जौनपुर, गुरूवार, 28 नवम्बर 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

मुंबई में बहुमंजिला इमारत में आग लगी, कोई हताहत नहीं

मुबई,(एजेंसी)। मुंबई के अंधेरी इलाके में बुधवार सुबह सात मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी (पश्चिम) स्थित चिंचन बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में सुबह 8.42 बजे आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए चार गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। सुबह करीब नौ बजे आग पर काबू पा लिया गया। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया, ''घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।'' आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं है।

उत्तर प्रदेश में डकैती का आरोपी 17 साल बाद महाराष्ट्र से पकड़ा गया

नई दिल्ली,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने ठाणे पुलिस के साथ मिलकर उप्र से डकैती और लूट के 2007 से फरार आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यहां जबरन वसूली निरोधक प्रकोष्ठ के अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सतीश बाबूलाल गुप्ता उर्फ घ्घ्सतीश तिवारी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के वागले एस्टेट इलाके में उसका पता चला और सोमवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अलमापुर गांव का निवासी गुप्ता उत्तरी राज्य में डकैती और लूट के दो मामलों में वांछित था। अधिकारी ने बताया कि उप्र एसटीएफ को ठाणे अपराध शाखा के जबरन वसूली निरोधक प्रकोष्ठ के सहयोग से कई स्थानों पर तलाशी अभियान के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।

सेना ने लापता व्यक्ति की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्ते तैनात किये

मणिपुर ,(एजेंसी)। इंफाल घाटी के सीमांत इलाके से दो दिन पहले लापता हुए एक व्यक्ति की तलाश के लिए सेना व्यापक तलाशी अभियान चला रही है। सेना के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। असम के कछार जिले के रहने वाले लैशराम कमलबाबू सिंह सोमवार दोपहर को कंगपोकपी के लेइमाखोंग सैन्य शिविर में काम करने के लिए घर से निकले थे और तभी से लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि सिंह इंफाल पश्चिम के खुखरुल इलाके में रहते थे।सेना के प्रवक्ता ने बताया कि वह लेइमाखोंग सैन्य शिविर में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) के साथ काम करने वाले एक ठेकेदार के लिए कार्य पर्यवेक्षक थे। प्रवक्ता के मुताबिक, जब सिंह के परिवार ने बताया कि वह 25 नवंबर की शाम को घर नहीं लौटे तो सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने सभी संसाधनों का उपयोग शुरू कर दिया। उन्होंने बताया, ''सीसीटीवी फुटेज को सावधानीपूर्वक खंगाला जा रहा है। उनके सहकर्मियों से बात की जा रही है ।

छात्र संघ की जगह युवा संसद के गठन पर विचार करें विश्वविद्यालय : मुख्यमंत्री योगी

प्रयागराज ,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे युवाओं के आने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आह्वान दोहराते हुए बुधवार को कहा कि विश्वविद्यालयों को यह विचार करना चाहिए कि छात्र संघ की जगह क्या युवा संसद का गठन कर सकते हैं। यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''इस युवा संसद के लिए हर कक्षा में तय होना चाहिए कि पहले ही वर्ष में कोई छात्र चुनाव लड़ने के लिए ना आने पाए।'' उन्होंने कहा, ''हर कक्षा में पहले वर्ष प्रतिनिधि चुने जाएं और फिर उन प्रतिनिधियों में तय किया जाए कि कौन दूसरे या तीसरे वर्ष या फिर स्नातकोत्तर कक्षा में चुनाव के मैदान के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और कौन चुनाव लड़ेंगे।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''जीवन के अलग–अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वे छात्र समाज को दिशा दे सकते हैं।'' योगी आदित्यनाथ ने एक घटना साझा की जिसमें उन्हें एक विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति मिला जिसकी उम्र बहुत अधिक थी। तभी उन्हें किसी ने बताया कि अमुक व्यक्ति छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और उसका बेटा उसी विश्वविद्यालय में बीए का छात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''इस घटना से मुझे लगा कि उस व्यक्ति ने छात्र संघ का पदाधिकारी बनने के लिए ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। आखिर इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में कोई लंबे समय तक रहना चाहता है तो वह शोध करे। छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी।

अमित शाह करेंगे महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर फैसला, नई दिल्ली में महायुति की बड़ी बैठक

मुबई,(एजेंसी)। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महायुति गठबंधन गुरुवार को अगली महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि तीन सहयोगी दल शिवसेना शिंदे, राकांपा अजित पवार और भाजपा– इस मामले पर चर्चा के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ ये बैठक होगी। कार्यवाहक सीएम ने ठाणे में अपने घर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी,

शिवसेना उसका समर्थन करती है, कल हम दिल्ली में अमित शाह के साथ सरकार गठन पर फैसला करेंगे। इसे भी पढ़ेंरू डींर्तीजतंरू देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय, एकनाथ शिंदे ने खुद को दौड़ से किया बाहर कई दिनों के राजनीतिक सस्पेंस के बाद, एकनाथ शिंदे ने बुधवार को देवेंद्र फडणवीस के लिए राज्य का अगला नेता बनने का रास्ता साफ कर दिया। महाराष्ट्र भाजपा द्वारा देवेन्द्र फडणवीस पर जोर देने के बावजूद, गठबंधन ने सीएम चयन पर औपचारिक घोषणा में देरी की है, गठबंधन सद्भाव बनाए रखने के लिए शिंदे को शामिल करने की मांग की है।

कांग्रेस ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के समक्ष उत्पन्न असुरक्षा के माहौल पर चिंता व्यक्त की

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए जा रहे असुरक्षा के माहौल पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की है , जिसमें धार्मिक नेता और बांग्लादेश संमिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की हाल ही में गिरफ्तारी का हवाला दिया गया है । एक बयान में, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग की और भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार पर देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दबाव बनाने का आग्रह किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए जा रहे असुरक्षा के माहौल पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है ।इस्कॉन भिक्षु की गिरफ्तारी इसका ताजा उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार को आवश्यक कदम उठाने और देश में

अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मनाएगी,ष एआईसीसी के मीडिया और प्रचार अध्यक्ष ने कहा । ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, ब्रह्मचारी मंगलवार को सुबह 11 बजे चटगांव छठे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के न्यायाधीश काजी शरीफुल इस्लाम के समक्ष पेश हुए। उनके वकीलों ने जमानत याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया। चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया है , जिसमें उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने वाले एक स्टैंड पर झंडा फहराने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने तब से मामले को आगे बढ़ाने में अनिच्छा व्यक्त की है, एक अल्पसंख्यक नेता ने कहा। इस बीच, गिरफ्तारी के जवाब में मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बयान में कहा गया।

आसन के फैसले के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है : धनखड़

नई दिल्ली,(एजेंसी)। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को सदन की परंपराओं का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अध्यक्ष द्वारा दिए गए फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। आरएस चेयरमैन ने सदस्यों से उत्पादकता का स्तर बढ़ाने और चर्चा, संवाद और नियमों के पालन का माहौल बनाने का आह्वान किया, भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से चौथी तिमाही की सदी के पहले दिन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। धनखड़ ने आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन उच्च सदन को संबोधित करते हुए कहा, अध्यक्ष के फैसले के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है, न कि मतभेदों का कारण। भारतीय संविधान को अपनाने की सदी की चौथी तिमाही के पहले दिन का यह ऐतिहासिक दिन है, आइए हम उत्पादकता का स्तर बढ़ाएं, आइए हम ऐसा माहौल बनाएं, जिसमें हम चर्चा, संवाद, विचार–विमर्श और नियमों का पालन करके उदाहरण पेश करें।ष अपने भाषण में, धनखड़ ने राज्यसभा की गरिमा को बनाए रखने के महत्व के बारे में अपने पहले के बयानों को दोहराया, इसे बुजुर्गों का सदन और संसद का ष्उच्च सदन कहा। संविधान को अपनाने के हालिया जश्न पर विचार करते हुए, उन्होंने सदस्यों को याद दिलाया कि इस मील के पत्थर ने सदन के भीतर जिम्मेदारी और सम्मान की भावना को बढ़ाने की मांग की। धनखड़ ने जोर देकर कहा कि अध्यक्ष द्वारा दिए गए फैसलों को मतभेद के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसे निर्देशों के रूप में देखा जाना चाहिए जो सम्मान की मांग करते हैं। उनकी टिप्पणी

ऐसे समय में आई है जब राज्यसभा संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विचार–विमर्श में लगी हुई है। उन्होंने कहा, ष्जैसा कि मैंने कई मौकों पर दोहराया है, मुझे लगा कि इस स्थिति को देखते हुए कि हम भारत के संविधान को अपनाने की सदी की आखिरी तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी है। इसलिए, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस सदन, बड़ों के सदन, उच्च सदन और राज्यों की परिषद को अच्छी तरह से स्थापित परंपराओं को प्रतिबिंबित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है कि अध्यक्ष के फैसले के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है न कि मतभेदों का कारण। धनखड़ ने कहा, ष्मैंने विस्तार से बताया है कि इस स्थिति में नोटिस क्यों स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

राहुल गांधी ने फिर साधा भाजपा पर निशाना, अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है

नई दिल्ली,(एजेंसी) अडानी रिश्वत मामला बुधवार को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गूंजा, जब दो वरिष्ठ वकीलों ने अडानी समूह के अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिकी आरोपों में छेद करने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई विपक्षी नेताओं द्वारा रिश्वत मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने के बाद संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और अन्य सभी कामकाज निलंबित कर दिए गए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए अपना आह्वान दोहराया और कहा कि उद्योगपति अमेरिकी अभियोजकों द्वारा उल्लिखित आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे? जाहिर है, वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छोटे–छोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि तथ्य यह है कि दो अभियोग दायर किए गए हैं, एक न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी द्वारा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा। इसलिए वे स्पष्ट

रूप से अमेरिकी अदालत के समक्ष ये तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल मुद्दा यह है कि ये अभियोग भारत के कारोबारी माहौल के संबंध में किस तरह का संदेश भेजते हैं। उन्होंने कहा कि नंबर दो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या कर रहा था? यदि अमेरिकी नियामक को अभियोग दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। यदि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को याद करें, तो अडानी समूह के संबंध में मुद्दे न केवल सार्वजनिक डोमेन में थे, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर आंदोलन किया जा रहा था या फैसला सुनाया जा रहा था। तो सवाल यह है कि नियामकों को विनियमित कौन करेगा? इसलिए, इसमें बड़े मुद्दे शामिल हैं और इसीलिए हम संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए निकाय के गठन की जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

नई दिल्ली,(एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया , जिसमें केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को ष्सनातन धर्म और उसकी संस्कृति की सुरक्षाष के लिए ष्सनातन धर्म रक्षा बोर्डष जैसा एक धार्मिक निकाय गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी । मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि न्यायालय नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अधिवक्ता अशोक कुमार के माध्यम से सनातन हिंदू सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारत सरकार ने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए विभिन्न निकायों या बोर्डों का गठन किया है। हालांकि, यह तर्क दिया गया कि सनातन धर्म के अनुयायियों,

जिन्हें हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है, के पास अपने अधिकारों और रीति–रिवाजों की रक्षा के लिए कोई समर्पित बोर्ड या सरकारी निकाय नहीं है, याचिका में कहा गया है। गठन की याचिका पर विचार यह भी कहा गया कि सनातनधहिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों से संबंधित समुदायों के सदस्य सनातन धर्म के खिलाफ विभिन्न प्रकार के हमले कर रहे हैं, जैसे सनातन धर्म के अनुयायियों को अन्य धर्मों में परिवर्तित करने का प्रयास करना, जो इसके अनुयायियों की परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ है। यह कहा गया कि हमारे देश में बहुसंख्यक लोग सनातनधहिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और इस तरह, उन्हें अपने धर्म से संबंधित सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का अधिकार है, जो भारत सरकार द्वारा कई वर्षों से प्रदान नहीं किया गया है। आलोचना की सरकार सनातनधहिंदू धर्म के अधिकारों और रीति–रिवाजों की रक्षा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

झारखंड में `अबुआ सरकार' की नयी पारी बृहस्पतिवार से शुरू होगी : हेमंत सोरेन

रामगढ,(एजेंसी)। झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद बृहस्पतिवार से 'अबुआ सरकार' (हमारी सरकार) की नयी पारी शुरू होगी। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ अपने दादा सोबरन सोरेन को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले में अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ''मैं अपने दादा सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने हर साल इस स्थान पर आता हूं।'' सोरेन ने अपने गांव वालों को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले अपनी सरकार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। नेमरा के लुकैयाटांड में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के गठन का काम जारी है। सोरेन ने ग्रामीणों से कहा, ''कल से 'अबुआ सरकार' (हमारी सरकार) की नयी पारी शुरू होगी। शपथग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को होना है। मैं आप सभी को इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी ने अबुआ सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत की है।' झामुमो के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार हेमंत के दादा सोबरन की साहूकारों ने उस समय हत्या कर दी थी जब झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन 15 वर्ष के थे। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में बंगाल सीमा के निकट घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित नेमरा शिबू सोरेन का जन्मस्थल भी है।

कैलाश गहलोत ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफ

नई दिल्ली,(एजेंसी) भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक हफ्ते से अधिक समय बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को भेजा। 17 नवंबर को दिल्ली के पूर्व मंत्री ने आप से इस्तीफा दे दिया। अपने फैसले का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी दिल्ली के लोगों से की गई महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता से आगे निकल गई हैं। उन्होंने शीशमहल जैसे कुछ विवादों हवाला देते हुए केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इससे हर किसी को संदेह होता है कि क्या हम अभी भी श्आम आदमीश होने में विश्वास करते हैं। गहलोत ने दिल्ली सरकार द्वारा अपना अधिकांश समय केंद्र के साथ लड़ने में खर्च करने और यमुना नदी को साफ करने में विफलता के खिलाफ भी बात की। इस बीच, आप नेताओं ने कहा कि गहलोत ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं और उनके पास भाजपा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, गहलोत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर

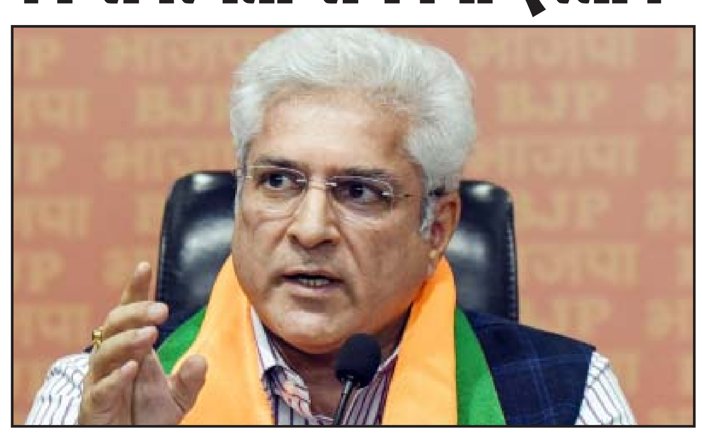

और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद गहलोत ने कहा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह फैसला रातोंरात और किसी के दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी किसी के दबाव में कुछ नहीं किया। मैं सुन रहा हूं कि एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह ईडी और सीबीआई के दबाव में किया गया था लेकिन यह सब गलत है।

संपादकीय

भारतीय चुनावों में महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या

लोकलुभावनवाद भारतीय राजनीति का एक अहम मंत्र है। ऐसा लगता है कि महिला मतदाता, बदले में, लोकलुभावन राजनीति की धुरी बनकर उभर रही हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का श्रेय महिला मतदाताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को दिया जा रहा है। लोकनीति–सीएसडीएस सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि महायुति गठबंधन को न केवल बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने पसंद किया, बल्कि उन महिलाओं ने भी पसंद किया जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था। झारखंड की मैया सम्मान योजना ने भी हेमंत सोरेन की पार्टी को आसानी से जीत दिलाने में मदद की। बंगाल, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस खुद को बहुत अधिक महत्व देती रही है, ने इस मामले में रास्ता दिखाया है, जहां लक्ष्मी भंडार अपनी शुरुआत से ही गेम–चेंजर के रूप में उभर रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से महिला मतदाताओं के लिए चिंता परोपकारी नहीं है। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों द्वारा आकार लेने वाले चतुर राजनीतिक गणित पर आधारित है। उदाहरण के लिए, महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि ने पार्टियों को महिलाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। |सेव त्मंक – म्कपजवतरू मानव युग के लिए हमारे संविधान पर पुनर्विचार आश्चर्यजनक रूप से, हस्तांतरण के रूप में वादा की गई राशि – मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति को देखते हुए एक छोटी राशि – महिलाओं को गुजारा करने में मदद करने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त होती है। क्या यह अंतर्निहित कृपालुता की संस्कृति का संकेत नहीं है? लाभार्थियों – महिलाओं – से आर्थिक उदारता के बदले में लाइन में आने की उम्मीद की जाती है जो पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, इस तरह के राजनीतिक लोकलुभावनवाद को प्रतिगामी के रूप में देखने का एक कारण है क्योंकि यह महिला मतदाताओं की सार्थक मुक्ति – भौतिक रूप से या अन्यथा – से असंबंधित है। महिला मतदाताओं को लक्षित करने वाले चुनावी लाभों में वृद्धि के साथ–साथ राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय नहीं किए गए हैं। संख्याएँ कहानी बयां करती हैं। लोकसभा में केवल 13.6ः सांसद महिलाएँ हैं। चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि राजनीतिक दलों में महिलाओं की उम्मीदवारी में उछाल से मेल नहीं खाती है। शायद इस दोहरेपन का सबसे अच्छा उदाहरण महिला आरक्षण विधेयक का भाग्य हैरू हालांकि यह संसद में पारित हो चुका है, लेकिन इसे लागू होने के लिए अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार करना होगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अप्रैल 2024 तक, राष्ट्रीय संसदों के लिए एक वैश्विक संगठन, अंतर–संसदीय संघ द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की मासिक रैंकिंग' में भारत 144वें स्थान पर था।

युद्ध में वृद्धि

पिछले हफ्ते जब रूस का यूक्रेन पर युद्ध 1,000 दिनों के भयावह मील के पत्थर को पार कर गया, तब भी युद्ध विराम की संभावनाएँ – स्थायी शांति की तो बात ही छोड़िए – कम होती दिख रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने क्रेमलिन द्वारा निर्धारित लाल रेखा को पार करते हुए यूक्रेन को रूस के भीतर गहरे लक्ष्यों पर अमेरिकी लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है। इसके तुरंत बाद, यूनाइटेड किंगडम ने भी यही कियारू यूक्रेनी सैनिकों द्वारा रूस के भीतर ब्रिटिश मिसाइलों को भी लॉन्च किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले कठोर प्रतिक्रिया की धमकी दी। फिर, रूस ने यूक्रेन पर एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की, जिसके बारे में पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि इसे पहले कभी नहीं

देखा गया। श्री पुतिन ने पहले यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर अन्य देशों के हथियारों के इस्तेमाल को मॉस्को पर युद्ध छेड़ने वाले अन्य देशों के समान बताया है। इस युद्ध के मैदान में होने वाली सभी घटनाओं पर डोनाल्ड ट्रम्प की छाया मंडरा रही है, जो जनवरी में श्री बिडेन से अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। श्री ट्रम्प ने कहा है कि वह अपने राष्ट्रपति पद के पहले दिन ही यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का इरादा रखते हैं। यह चुनावी बयानबाजी हो सकती है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने नवंबर की शुरुआत में फिर से आश्चर्यजनक चुनाव जीता, ने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा का निर्माण आंशिक रूप से नए युद्ध शुरू न करने और पुराने युद्धों को समाप्त करने के अपने वादे पर किया है। |सेव त्मंक – म्कपजवतरू मानव युग के लिए हमारे संविधान पर पुनर्विचार फिर भी, जबकि युद्ध का अंत सीधे तौर पर शामिल सभी पक्षों और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए स्वागत योग्य समाचार होना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं है कि श्री ट्रम्प रूस और यूक्रेन को शांति समझौते के हिस्से के रूप में किस बात पर सहमत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल, रूसी सेना धीरे–धीरे लेकिन लगातार पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रही है। श्री ट्रम्प के उप–राष्ट्रपति–चुनाव, जे. डी. वेंस ने कहा है कि शांति समझौते में यूक्रेन को अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ सकता है – अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भूमि का लगभग 20ः – जो वर्तमान में रूस के कब्जे में है और दोनों सेनाओं को अलग करने के लिए एक बफर जोन की स्थापना। यह स्थिति अभी तक यूक्रेनी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है। कई मायनों में, हाल के दिनों में लड़ाई में वृद्धि दोनों पक्षों द्वारा किसी भी वार्ता के शुरू होने से पहले जमीन पर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास प्रतीत होता है ताकि वे अपने सौदेबाजी के कौशल को मजबूत कर सकें। संयम बरतने के बजाय, रूस और यूक्रेन को हमले बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह अगले कुछ हफ्तों को विशेष रूप से अस्थिर अवधि बना सकता है। दुनिया चिंता में है।

मानव युग के लिए हमारे संविधान पर पुनर्विचार

परिवर्तन करिश्मा का एक तत्व प्रदान करता है, रोजमर्रा की जिंदगी की दिनचर्या के लिए एक रंगमंच की भावना प्रदान करता है। लेकिन, हाल ही में, परिवर्तन की अवधारणा ही समस्याग्रस्त हो गई है, विरोधाभासों और विडंबनाओं के अधीन है।इस सप्ताह, हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें इसे कैसे देखना चाहिए? कोई राष्ट्रीय आंदोलन की व्यापक बहसों के भीतर बहस को खोजने की कोशिश करता है। तो आइए संविधान को आमूलचूल परिवर्तन के केंद्र के रूप में देखें। |सेव त्मंक – त्नेपं–नतंपदम युद्ध में वृद्धि पर संपादकीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन का एक सभ्यतागत दृष्टिकोण था। परंपरा और संग्रहालय पर शुरुआती बहसों पर विचार करें। भूविज्ञानी और कला समीक्षक आनंद कुमारस्वामी द्वारा संचालित बहसों में दावा किया गया कि पश्चिम को परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है, स्मृति का तो और भी कम। इसने संग्रहालयों की स्थापना के खिलाफ तर्क दिया, यह दावा करते हुए कि यह स्मृति का अत्याचार पैदा करेगा, जबकि मौखिक स्मृति ने ऐसी परंपराएँ बनाईं जो गतिशील थीं। कुमारस्वामी ने तर्क दिया कि स्वदेशी आंदोलन को संग्रहालय के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ना चाहिए क्योंकि यह श्झूठी स्मृतिश है, जो जीवन का एक टैक्सीडर्मी है। |सेव त्मंक – भारतीय चुनावों में महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या पर संपादकीय आंदोलन और आगे बढ़ गया– कुमारस्वामी ने 'पोस्ट–इंडस्ट्रियल' शब्द गढ़ा। आज, लोग इस शब्द को डैनियल बेल की द कमिंग ऑफ पोस्ट–इंडस्ट्रियल सोसाइटी से जोड़ते हैं। बेल ने इस शब्द को उधार लिया और इसे संक्षिप्त किया। लेकिन कुमारस्वामी ने प्रकृति, शिल्प और उद्योग के सह–अस्तित्व के लिए लेबल का इस्तेमाल किया था– एक ऐसा मिश्रण जिसकी आज हमें सख्त जरूरत है। दूसरी ओर, पैट्रिक गेडेस जैसे जीवविज्ञानी मानते हैं कि संविधान में केवल ब्रह्मांड, आजीविका और समय और ऊर्जा के बारे में कठोरता की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक त्रासदी है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने संविधान में ब्रह्मांडीय समय और एन्ट्रॉपी के विचारों को शामिल नहीं किया। नतीजतन, इसका बर्बादी और न्याय के बीच कोई संबंध नहीं था। जैसा कि वैज्ञानिक सी वी शेषाद्रि ने कहा, हमें बर्बादी और बर्बाद समाज के लोगों के बीच संबंध का कोई बोध नहीं था। के–ड्रामा से प्रेरित होकर भारतीय दम्पति ने रखा बच्चे का नाम यह हमें इस ओर ले जाता है कि हम आज बदलाव और संविधान को कैसे देखते हैं। संविधान के प्रमुख अधिवक्ताओं ने संवैधानिक परिवर्तन के बारे में रूढ़िवाद की वकालत की। लेकिन एक नया मुद्दा जो उनके सामने खड़ा है वह है एंथ्रोपोसीन।एंथ्रोपोसीन' शब्द डच वैज्ञानिक पॉल क्रुटजेन द्वारा गढ़ा गया था। यह भूवैज्ञानिक काल के लिए एक लेबल है जब मनुष्य एक भू–राजनीतिक शक्ति बन गया है और यह पृथ्वी को उसके द्वारा पहुँचाए गए नुकसान की स्वीकारोक्ति है। भारत के वीजा संचालन में व्यवधान से हमें भी नुकसान हो रहा है एक संविधान को युद्ध, नरसंहार, वन हानि या अप्रचलन के बावजूद इस स्वीकारोक्ति और अपराध बोध का सामना करना पड़ता है। एंथ्रोपोसीन मानव अधिकारों और उसकी संकीर्णता की सीमाएँ निर्धारित करता है। क्या हम कम से कम अमेरिकी भारतीयों के नरसंहार को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम मोनोकल्चरल वानिकी के बारे में कोई प्रश्न देख सकते हैं? किसी को अधिकारों की सीमाओं को एक कार्यशील अवधारणा के रूप में स्वीकार करना होगा और कॉमन्स जैसे शब्दों के इर्द–गिर्द शब्दों की एक शब्दावली बनानी होगी। अपने मौन ब्रह्मांड के साथ कॉमन्स मानव अधिकारों की तुलना में पारिस्थितिकी का अधिक बड़ा रक्षक है। जैसा कि डेसमंड टूटू के आयोग ने कहा, किसी को नैतिक मरम्मत और नैतिक उपचार दोनों की आवश्यकता होती है। किसी को संकट से सामान्य स्थिति में नए संक्रमण की कल्पना करनी होगी। इस संदर्भ में किए गए प्रस्तावों में से एक नया यूनेस्को है। कन्नड़ लेखक यू आर अनंतमूर्ति ने सुझाव दिया कि हमें अनुवाद के नए तरीकों की आवश्यकता है, जहाँ स्थानीय भाषा सीधे पहुँच में हो। इसके लिए एक नया यूनेस्को आदर्श होगा। राष्ट्र राज्य द्वारा दी जा रही जानकारी से कहीं अधिक जटिल क्षेत्र की अवधारणा की आवश्यकता है। वास्तव में, हमें वर्तमान राष्ट्र राज्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी से परे क्षेत्रों की एक बुनाई की आवश्यकता है। स्थानीय भाषा को अपनी केंद्रीयता पर लौटना होगा। मानव जाति को राष्ट्र राज्य से आगे जाना होगा और पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र दोनों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। यह मांग करता है कि मनुष्य एक नई नैतिकता और शासन के नए शब्दों को पुनर्जीवित करे। वैज्ञानिक सी वी शेषाद्रि ने सुझाव दिया कि संविधान को सभ्यतागत कॉमन्स, नागरिक शास्त्र, पाठ्यक्रम, नागरिकता से लेकर स्वराज तक फिर से तैयार किया जाना चाहिए। संविधान को कानून, नैतिकता और जिम्मेदारी के पैमाने पर फिर से काम करना होगा। समय यहाँ ट्रस्टीशिप का एक रूप बन जाता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी के अलग–अलग पैमाने पहनता है। हमें शिक्षाशास्त्र और ज्ञानमीमांसा की एक नई अवधारणा को जोड़ना होगा। विश्वविद्यालय को संविधान के साथ बदलना होगा। हमें ऐसे संविधान के लिए पवित्रता की अवधारणा का आविष्कार करना होगा, बुराई और हिंसा की नई भावना प्रदान करनी होगी, जैसा कि राजनीतिक दार्शनिक हन्ना अरेंड्ट ने संकेत दिया था। मानवता के नाटकीय क्षण के दौरान, संविधान एक संकीर्ण इकाई नहीं हो सकता। इसके लिए अलग तरह की कहानियों और अवधारणाओं, अलग तरह की कहानी कहने की जरूरत है, ताकि मिथक एक नई अचेतनता पैदा कर सकें। पुरानी कहानियाँ काम नहीं आएंगी। यह केवल मानवजाति बनाने का सवाल नहीं है। नए रंगमंच में, नए कथानक और नई जिम्मेदारियाँ खुलकर सामने आती हैं। लेकिन हमारे संविधान में प्रकृति, समय, नैतिकता या आदिवासियों के भाग्य की बहुत कम समझ है। जटिलता को जोड़ने के लिए इसे स्वदेशी और स्वराज की नई भावना की जरूरत है। फिर भी, किसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान को बनाए रखने वाली समुदाय की भावना को किसी गैर–जिम्मेदार समूह द्वारा अपहृत न किया जाए। यही कारण है कि किसी को सूक्ष्म स्तर पर संविधान की भावना को बनाए रखते हुए वृहद स्तर पर संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ता है। संविधान के साथ छेड़छाड़ किए बिना शैक्षणिक, राजनीतिक और नैतिक संकट से निपटना होगा।

बांग्लादेश में भारत के वीजा संचालन में व्यवधान से हमें भी नुकसान हो रहा है

भारत और बांग्लादेश के बीच इतिहास, भाषा, संस्कृति और कई अन्य समानताओं के गहरे बंधन हैं। द्विपक्षीय संबंधों की उत्कृष्ट प्रकृति संप्रभुता, समानता, विश्वास और समझ पर आधारित एक व्यापक साझेदारी में परिलक्षित होती है। यह साझेदारी पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लिए द्विपक्षीय संबंधों के एक मॉडल के रूप में विकसित हुई है।" ये शब्द भारत के विदेश मंत्रालय के हैं, जो 2024 के ष्भारत–बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों पर संक्षिप्त विवरणष में प्रकाशित हुए थे। |सेव त्मंक – म्कपजवतरू मानव युग के लिए हमारे संविधान पर पुनर्विचार वर्तमान में, दोनों देशों के बीच तीन रेलवे ट्रेनें चल रही हैं – (1) मैत्री एक्सप्रेस (2008 से, कोलकाता और ढाका को जोड़ती है)य (2) बंधन एक्सप्रेस (2017 से, कोलकाता और खुलना को जोड़ती है)य और (3) मिताली एक्सप्रेस (जून 2022 से, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच)। इसके अतिरिक्त, भारत और बांग्लादेश के बीच पाँच बस सेवा मार्ग चालू हैं – कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी को ढाका और आगे खुलना तक जोड़ते हैं। मैंने 2020 में कोविड–19 महामारी फैलने से कुछ हफ्ते पहले ही खुलना के लिए ट्रेन ली थी और यह जानकर भारतीयों को आश्चर्य होगा कि सीमा पार से कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 1965 के युद्ध के दौरान बंद होने के बाद 2017 में इस ट्रेन लिंक को फिर से शुरू किया गया था। |सेव त्मंक – त्नेपं–नतंपदम युद्ध में वृद्धि पर संपादकीय बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2023–24 में भारत को 2 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। वित्त वर्ष 2023–24 में, कुल द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन डॉलर बताया गया है, जिसका अर्थ है कि यह भारत के पक्ष में काफी हद तक झुका हुआ है। विदेश मंत्रालय के नोट में कहा गया है कि भारत एक मेडिकल मरीज के साथ भारत आने के लिए तीन बांग्लादेशियों को मेडिकल अटेंडेंट वीजा जारी करता है – एक अत्यधिक उदार प्रक्रिया जो बांग्लादेश के लिए विशिष्ट रूप से विस्तारित है। बांग्लादेश में हमारा वीजा संचालन दुनिया भर में भारत द्वारा संचालित सबसे बड़ा वीजा संचालन है, मेजबान देश में मौजूद आवेदन केंद्रों, प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की मात्रा के साथ–साथ संसाधित और जारी किए गए वीजा की संख्या के संदर्भ में। |सेव त्मंक – भारतीय चुनावों में महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या पर संपादकीय बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2023–24 में भारत को 2 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। वित्त वर्ष 2023–24 में, कुल द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन डॉलर बताया गया है, जिसका अर्थ है कि यह भारत के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ है। विदेश मंत्रालय के नोट में कहा गया है कि भारत एक मेडिकल मरीज के साथ भारत आने के लिए तीन बांग्लादेशियों को मेडिकल अटेंडेंट वीजा जारी करता है – एक अत्यधिक उदार प्रक्रिया जो बांग्लादेश के लिए विशिष्ट रूप से विस्तारित है। बांग्लादेश में हमारा वीजा संचालन दुनिया भर में भारत द्वारा संचालित सबसे बड़ा वीजा संचालन है, मेजबान देश में मौजूद आवेदन केंद्रों की संख्या, प्रति दिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की मात्रा और संसाधित और जारी किए गए वीजा की संख्या के संदर्भ में। |सेव त्मंक – म्कपजवतरू के–ड्रामा से प्रेरित होकर भारतीय दम्पति ने रखा बच्चे का नाम दूसरी ओर, भारत आने के लिए पाकिस्तानियों को क्या करना होगा, यह अक्टूबर 2024 में मेरे दोस्तों द्वारा लाहौर से बेंगलुरु की यात्रा के माध्यम से समझाया जा सकता है। उनमें से एक गुरुवार की रात को अटारी–वाघा सीमा से पैदल चलकर अमृतसर से बेंगलुरु पहुंचा। अगले दिन, वह बेंगलुरु में अपने प्रवेश को दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पाकिस्तानियों को शहर–विशिष्ट वीजा दिया जाता है जिसके लिए उन्हें प्रवेश और निकास पर प्रत्येक शहर के पुलिस स्टेशनों पर पंजीकरण कराना होता है। उसके अगले दिन, शनिवार को, वह फिर से अपने निकास को दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि स्टेशन रविवार को बंद रहेगा। वह रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ और सोमवार को उसे वहाँ के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना था। और इसी तरह। मैं अपने दोस्त के साथ सहानुभूति रख सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की मेरी कुछ यात्राओं पर मुझे भी इसी तरह के "रिपोर्टिंग" वीजा दिए गए हैं। वे लोगों को आने से हतोत्साहित करने के लिए होते हैं और यह उन लोगों की किस्मत है जो वास्तव में वीजा प्राप्त करते हैंय अधिकांश लोगों को मना कर दिया जाता है। यह कठोरता पारस्परिक है और दोनों पक्ष वही करते हैं जो दूसरे देश करते हैं। लगभग 40,000 पाकिस्तानी पर्यटकों की तुलना में लगभग 25 लाख बांग्लादेशी पर्यटक सालाना भारत आते हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में, बांग्लादेशी भारत आने वाले पर्यटकों में सबसे आगे होंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से ऊपर है, जो इन तीन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या को देखते हुए उल्लेखनीय है। 2010 तक बांग्लादेशी पर्यटकों की संख्या लगभग पाँच लाख प्रति वर्ष थी और उससे पहले के तीन वर्षों में यह संख्या लगभग इसी के आसपास थी। फिर 2014 में यह दोगुनी होकर लगभग 10 लाख हो गई और नरेंद्र मोदी के दशक में यह फिर से दोगुनी हो गई है। आने वाले बांग्लादेशियों की संख्या इस तथ्य के लिए भी उल्लेखनीय है कि उसी अवधि में भारत में सत्ता में राजनीतिक दल की ओर से बांग्लादेशियों के प्रति अवमानना घ्घ्की बयानबाजी रही है। यहां तक घ्घ्कि हाल ही में समाप्त हुए चुनाव अभियान में भी, भाजपा नेतृत्व की ओर से मतदाताओं को संदेश ष्बाहरी लोगोंष के खतरे से भरा हुआ था। इस निरंतर डराने–धमकाने को देखते हुए, अधिकांश भारतीय शायद सोचेंगे कि बांग्लादेश के साथ वीजा व्यवस्था वैसी ही है जैसी कि पाकिस्तान के साथ है। ऐसा नहीं है और वास्तविक संख्याओं पर एक नजर डालने से पता चलता है कि भाजपा ने बांग्लादेशियों के प्रति अवमानना घ्घ्की है। जैसा कि पिछली सरकारों ने बांग्लादेश के लोगों की अधिक मुक्त आवाजाही की अनुमति देकर उसके साथ संबंधा बनाने में बुद्धिमानी भरे कदम उठाए थे। यह, दोहराना चाहूंगा, भारत के लिए फायदेमंद है जैसा कि आंकड़े बताते हैं। बेशक, दोनों देशों के बीच आवाजाही उतनी मुफ्त नहीं है जितनी दूसरे पड़ोसी के साथ है, जिसके बारे में हमारे विदेश मंत्रालय के नोट में लिखा हैरू "भारत और नेपाल सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, खुली सीमा और लोगों के बीच गहरे संपर्कों की विशेषता वाले घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं"। भाषा बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों का वर्णन करने वाली भाषा के समान है, लेकिन एक अंतर है। वह निश्चित रूप से यह तथ्य है कि नेपाल के साथ हमारी एक खुली सीमा है और दोनों तरफ के नागरिकों को दूसरे देश में जाने या रोजगार खोजने के लिए वीजा और यहां तक का पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है।

हर चुनाव अलग होता है कोई एक फॉर्मूला सभी पर फिट नहीं बैठता

कोमल शर्मा

महाराष्ट्र के हाई–प्रोफाइल विधानसभा चुनावों और झारखंड के कम चर्चित चुनावों के नतीजे दिलचस्प हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि मतदाताओं ने बहुत अलग–अलग परिस्थितियों और बहुत अलग–अलग राजनीतिक संस्कृतियों और सामाजिक तथा आर्थिक इतिहासों में जानबूझकर चुनाव किए हैं। कथित तौर पर "बताएंगे तो काटेंगे" और "एक हैं तो सुरक्षित हैं" जैसे भड़काऊ नारों ने महाराष्ट्र में मतदाताओं को उत्साहित किया, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोलबंद किया और यह काम कर गया, जैसा कि जनादेश से साबित होता है। झारखंड में भड़काऊ हिमंत बिस्वा शर्मा और कट्टर शिवराज सिंह चौहान की मदद से आरएसएस का यही फॉर्मूला विफल हो गया। |सेव त्मंक – म्कपजवतरू मानव युग के लिए हमारे संविधान पर पुनर्विचार नतीजों ने महाराष्ट्र में दो नए नेताओं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को जन्म दिया, जिससे दोनों को शिवसेना और एनसीपी को विभाजित करने के लिए "गद्दार" (देशद्रोही) के आरोप से मुक्त कर दिया गया और उन्हें वंशवादी उद्धव ठाकरे और संस्थापक नेता शरद पवार की जगह लेने के लिए निर्णायक जनादेश मिला। यह चुनाव दोनों पार्टियों के लिए एक संस्कार था और मूल पार्टियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली विचारधारा, मूल्यों, जातियों, समुदायों, मतदाताओं के नए मशालवाहकों ने नए नेताओं का समर्थन किया। |सेव त्मंक – त्नेपं–नतंपदम युद्ध में वृद्धि पर संपादकीय महायुति (भाजपा–शिवसेना–राकांपा) के लिए भारी जनादेश था, जो एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में उभरा है, जिसका यह भी अर्थ है कि महा विकास अघाड़ी (पूर्व में एकीकृत शिवसेना–राकांपा– कांग्रेस) एक अप्राकृतिक अवसरवादी गठबंधन था। महाराष्ट्र में नई सरकार तीन पैरों वाली कुर्सी होगी। भाजपा के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे और अजित पवार दूसरे दर्जे के नेता के रूप में कैसे विकसित होते हैं, यह अगले पांच वर्षों में पता चलेगा। दूसरा परिवर्तन, जिसका परिणाम सबसे अधिक वांछित था लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, यह देखना है कि क्या भाजपा अंततः महाराष्ट्र की प्रमुख पार्टी बन पाती है, जिस स्थिति पर दशकों से कांग्रेस का कब्जा है। तब तक, भाजपा, जो कि कड़ी मेहनत करने वाली, निर्दयी और दृढ़ है, को अभी बहुत आगे जाना है। |सेव त्मंक – भारतीय चुनावों में महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या पर संपादकीय झारखंड में हेमंत सोरेन को विभिन्न आदिवासी समुदायों का नेता घोषित किया गया, जिन्होंने 81 सदस्यीय विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 27 सीटें जीतीं। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतीत में आदिवासी प्रतिनिधित्व खंडित था और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और श्री सोरेन के नेतृत्व में यह एकीकृत हो गया है। गिरफ्तारी और कारावास से गुजरने के बाद, 2024 का जनादेश नेता और भारत ब्लॉक के भीतर उनके सापेक्ष वजन के लिए एक नई शुरुआत है। महाराष्ट्र के नतीजों ने धर्मनिरपेक्ष–उदारवादी– प्रगतिशील गठबंधन की इस आशंका की पुष्टि की कि कांग्रेस एक खराब टीम प्लेयर है, लालची है, हालांकि अपनी महत्वाकांक्षाओं को परिणामों में बदलने की क्षमता से रहित है, और राहुल गांधी का लापरवाह, अस्थिर नेतृत्व एक बोझ है। जबकि कांग्रेस, उसकी क्षमताओं और उसके नेतृत्व का आकलन पूरी तरह से सही है, महा विकास अघाड़ी बनाम महायुति के विनाशकारी प्रदर्शन का दोष पूरी तरह से भव्य पुरानी पार्टी पर नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज और भारत के सबसे चतुर राजनेता और सबसे बेहतरीन जोड़ीदार शरद पवार भी दोषी हैंरू उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनका युग समाप्त हो चुका है। इसका नतीजा पवार सीनियर के लिए सबसे कड़वी गोली साबित होगा, क्योंकि लोगों ने उनके उत्तराधिकारी अजीत पवार को चुन लिया है। दोनों राज्यों में मतदाताओं ने प्रोत्साहनों के लिए एक अलग प्राथमिकता दिखाई, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मतदाताओं ने अन्य राज्यों में क्या चुना है। मतदाताओं द्वारा निर्णय लेने के तरीके में एक पैटर्न आकार ले रहा है, जो बताता है कि उग्र हिंदुत्व की कपटी अपील को कम करने के लिए चीनी की मोटी परत की आवश्यकता है। चीनी की परत चढ़ाने का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में स्पष्ट था, और हरियाणा और अब महाराष्ट्र के चुनावों में इसकी पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, महिलाओं को सीधे नकद हस्तांतरण, बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये का वजीफा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड, एक वजीफा जो अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए कोचिंग की अत्यधिक महंगी लागत को आंशिक रूप से पूरा करेगा, श्री सोरेन के लिए कारगर साबित हुआ, जिससे यह पुष्टि हुई कि यह पैटर्न सभी राज्यों में लागू है, चाहे वे भाजपा शासित हों या नहीं। इस चरण में दो राज्य चुनाव, हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में पहले के चुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के साथ–साथ हुए 46 उपचुनाव स्पष्ट रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या इन चुनावों ने पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया और भाजपा की सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी पहचान की राजनीति और उसके इस विश्वास के साथ–साथ स्वीकार्यता की पुष्टि की कि वह भारत में हिंदुत्व के वर्चस्व को स्थापित करने की हकदार है? दूसरा सवाल जो महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव नहीं उठाता है वह यह हैरू क्या आरएसएस में चुनाव के नतीजों को बदलने की क्षमता है? यह धारणा कि आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और प्रभावशाली लोगों के अपने विशाल नेटवर्क को रोककर रखा और महाराष्ट्र में इस सेना को तैनात किया, इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में यह विफल रहा। अगर नतीजों में अंतर से कोई निष्कर्ष निकालना है, तो उसे स्थानीय स्तर के अंतरों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करने वाली विशिष्टताएँ। यह भाजपा–आरएसएस की राजनीति के विशिष्ट चरित्र और विभिन्न राज्यों के मतदाताओं से मेल खाने के लिए अपने अभियानों को अनुकूलित करने की क्षमता पर सवाल उठाता है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में राजनीति को बिना किसी भिन्नता के एक ही प्रारूप के आधार पर संचालित नहीं किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि क्षेत्रवाद फल–फूल रहा है, लेकिन समान–आधिपत्यवादी हिंदुत्व के बारे में यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने कोई नया क्षेत्र हासिल नहीं किया है।

एसकेडी एकेडमी का वार्षिक खेल और सांस्कृतिक उत्सव : एकना स्टेडियम में होगा भव्य आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एसकेडी एकेडमी अपनी पांचों शाखाओं के छात्रों के लिए एक यादगार अनुभव लेकर आ रहा है। पहली बार, लखनऊ की शान एकना स्टेडियम में एक भव्य वार्षिक खेल और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश और लखनऊ के विद्यालयी खेल इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह भव्य वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम रविवार, 1 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।

5,000 से अधिक छात्रों की प्रस्तुति और 10,000 से अधिक दर्शक

इस भव्य आयोजन में 5,000 से अधिक छात्र विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही, 10,000 से अधिक अभिभावक और मेहमान इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे।

ओलिंपिक विजेता समेत कई नामचीन एथलीट होंगे शामिल

कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए ओलिंपिक खेलों के विजेता समेत कई नामचीन एथलीटों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रीगण और स्थानीय विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को सम्मानित करेंगे।

एसकेडी एकेडमी के निदेशक श्री मनीष सिंह का सन्देश

एसकेडी एकेडमी के निदेशक श्री मनीष सिंह ने कहा, ष्हमारे लिए यह एक गर्व का क्षण है कि हम एकना स्टेडियम जैसे प्रतिष्ठित स्थल पर अपना वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह आयोजन हमारे छात्रों के लिए एक मंच होगा जहां वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। साथ ही, इस आयोजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले एथलीटों की उपस्थिति हमारे छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगी।

कार्यक्रम की थीमरू जलवायु परिवर्तन, एकता और वैश्विक भाईचारा

इस वर्ष के वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की थीम जलवायु परिवर्तन, एकता और वैश्विक भाईचारा है। इस थीम के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने और एकता का महत्व समझाने का प्रयास किया जाएगा।

फिर सज गई शाही पुल की गुमटियों पर दुकाने नगर पालिका परिषद बेखबर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। शहर के बीचो–बीच स्थित गोमती नदी पर शाही पुल है जिसपर रोज लाखो लोगो का आना जाना होता है,पुराना पुल होने की वजह से पहले से ही यह पुल सकरा है ,जिस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एकल मार्ग बनकर किसी तरीके से आने जाने वाले राहगीरों के लिए रास्ते को सुलभ बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण की जद में यह है यहां इसके गुमटियों झरोखों पर सालों से यहां पर इसमें स्थित गुमटियों पर दुकान नहीं लगती थी। लेकिन पिछले महीनो से यह दुकान फिर से सज गई जिसकी वजह से इस पर अतिक्रमण बढ़ गया है शहर के ओलंदगंज से चहारसू की तरफ जाने के लिए लोगों को दिनभर काफी मशक्कत व मेहनत करनी पड़ती है।

स्कूल की बस, मोटरसाइकिल सवार ई रिक्शा वाले, दिनभर जाम में फंसे रहते हैं जाम की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता उसका मुख्य कारण शाही पुल पर सजी हुई दुकान व अवैध अतिक्रमण हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ कपड़े वाले प्लास्टिक का सामान बेचने वाले ,बैग बेचने वाले, ठेले ,खोमचे वालों ने शाही पुल पर अतिक्रमण कर रखा है। इस बाबत जब नगर पालिका के जे ई पवन कुमार से उनकी राय जानना चाहा तो उनका फोन नहीं उठा।

टाटानगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस व बाघ एक्सप्रेस का जौनपुर भंडारी स्टेशन पर हुआ ठहराव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद वासियों को मिलने जा रही है एक और नई सौगात अब आप सीधे जौनपुर से अमृतसर व टाटानगर जा सकते है। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव के अथक प्रयास से भारत सरकार के रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने टाटानगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस की जौनपुर जंक्शन पर ठहराव की स्वीकृति प्रदान कर दी है। गाड़ी स. 18103 जो टाटानगर से वाराणसी, जौनपुर होते हुए अमृतसर जाती हैं। और गाड़ी स. 18104 जो अमृतसर से अयोध्या, जौनपुर होते हुए टाटानगर जाती हैं। लेकिन इन दोनों ट्रेनों ठहराव जौनपुर जंक्शन पर नहीं था। जनपद वासियों को अमृतसर जाने के लिए और टाटानगर जाने के लिए अगल–बगल के जनपदो से ट्रेन पकड़ना पड़ता था। क्योंकि जौनपुर जनपद से कोई ट्रेन सीधे अमृतसर और टाटानगर की नहीं थी। खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चन्द्र यादव ने बाघ एक्सप्रेस के जौनपुर जंक्शन पर ठहराव के लिए 14 जुलाई 2024

को रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव से मिलकर आग्रह किया था कि बाघ एक्सप्रेस का ठहराव जौनपुर जंक्शन पर किया जाए।

रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव ने खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की मांगों को स्वीकार करते हुए जौनपुर जंक्शन पर गाड़ी स 18103 /18104 टाटानगर अमृतसर एक्सप्रेस के ठहराव की स्वीकृति कर दी गई है।

गाड़ी स.18103 टाटानगर, बोकारो, वाराणसी होते हुए प्रातः 9. 02 AM पर जौनपुर जंक्शन पर ठहराव होगा फिर यही से अयोध्या होते हुए अमृतसर जाएगी।

गाड़ी स. 18104 अमृतसर, जालंधर, लुधियाना होते हुएं प्रातः 7.51 AM पर जौनपुर जंक्शन पर ठहराव होगा फिर वाराणसी होते हुए टाटानगर जायेगी। राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों का ठहराव जौनपुर जंक्शन पर अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा । इन ट्रेनों के ठहराव से जनपद वासियों और व्यापारी बंधुओ को काफी सुविधा मिलेगी। जनपद वासियों की तरफ से भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को इन दोनों ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति प्रदान करने के लिए बहुत–बहुत आभार। उक्त जानकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के मीडिया प्रभारी मनीष श्रीवास्तव ने दी।

75 वें संविधान दिवस पर संविधान सभा के सदस्य की 110 वीं जयंती मनी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। विमला बहन, सुधीर भाई गोयल, विजय कुमार आदि हुए चौधरी रणवीर सिंह नेशनल इंटीग्रेशन पीस एंड हार्मनी अवॉर्ड से किया गया सम्मानित. उक्त जानकारी देते हुए विनोबा विचार प्रवाह के सूत्रधार रमेश भइया ने बताया कि भारत देश की आजादी के लंबे चले आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ अनेक भारत मां के वीर सपूतों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में हजारों का नाम इतिहास में इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी श्रृंखला में रोहतक हरियाणा में 26 नवंबर 1914 को जन्मे चौधरी रणवीर सिंह जी का भी नाम है जो एक प्रसिद्ध शख्सियत के रूप में लोकसभा ,राज्यसभा और विधानसभा के अलावा हरियाणा राज्य बनने से पहले पंजाब राज्य सरकार के मंत्री भी रहे । वे अंग्रेजों के शासनकाल में आठ विभिन्न जेलों में बंद रहे इन सब राजनीतिक पदों के अलावा चौधरी रणवीर सिंह भारत की महत्वपूर्ण संविधान सभा के माननीय सदस्य भी रहे थे। रोहतक में एक बड़े स्थान पर उनकी समाधि स्थल पर हर वर्ष 25 नवंबर को एक सद्भावना यात्रा का आयोजन और प्रत्येक वर्षों 26 नवंबर को श्रद्धांजलि देने वालों का मेला जैसा लगता है।जहां पर भाई जी डा एस एन सुब्बाराव जी स्वयं प्रत्येक प्रार्थनासभा को आयोजित करते थे। देश में समाजसेवा के क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों को अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता रहा है।

कल 75 वें संविधान दिवस पर चौधरी रणवीरसिंह जी की 110 वीं जयंती पर हजारों लोगों के मध्य हरियाणा युवा शक्ति के बैनर तले सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन राष्ट्रीय युवा योजना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नीरज कुमार पटना बिहार द्वारा आयोजित की गई।जिसमें मुख्य आयोजक राष्ट्रीय युवा योजना के श्री सुरेश राठी, हिमाचल के श्री वी एस पवार, श्री जगदीश चौधरी, श्री नरेंद्र यादव, आगरा के श्री चंद्र मोहन पाराशर आदि उपस्थित रहे। मुख्य आकर्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की चौथी पीढ़ी के हिमाचल से आए 11 बच्चे रहे।जिनके हाथ में तिरंगा झंडा और नारे लगाए।

सम्मान की श्रृंखला में चौधरी रणवीर सिंह नेशनल इंटीग्रेशन पीस अवॉर्ड से मुख्य रूप से पीड़ितों दिव्यांग जनों और बुजुर्गों वंचितों की सेवा का काम करने वाले सेवाधाम उज्जैन के प्रमुख फादर टैरेसा के नाम से प्रख्यात डा सुधीर भाई गोयल को सम्मानित किया जाना तय था।फ्लाइट छूट जाने से न पहुंच पाने की स्थिति में दिल्ली हरिजन सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीभगवान शर्मा ने सम्मान ग्रहण किया। इसी श्रृंखला में बिहार के मध्यप्रदेश के श्री सुधीर भाई गोयल श्री नीरज कुमार, हिमाचल के श्री वी एस पवार, राजस्थान की पिंकी कौशिक बहन दिल्ली के श्रीभगवान शर्मा , जमनालाल बजाज अवॉर्ड एवं अनेक पुरस्कारों से सम्मानित से उत्तर प्रदेश की विमला बहन को श्रीमती आशा हुड्डा और चौधरी साहब के सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी द्वारा सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह व शाल से सम्मानित किया गया। आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन हरियाणा राज्य का गौरव माना जाता है। लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रार्थना सभा की परम्परा हमारे भाई जी सुब्बाराव जी ने डाली है।जो अच्छे ढंग से सुरेश राठी के कारण निर्वाह हो रही है। देश भर में गांधी विनोबा का काम करने वालो का अपना कार्यक्रम है। सबके लिए खुला है मंदिर यह है हमारा सामूहिक रूप से गाया गया।सभी का आभार ट्रस्टी श्री जगदीश चौधरी द्वारा दिया गया।स्वागत श्री जगवीर साजवान धर्मेंद्र भाई द्वारा किया गया। संचालन श्री नरेंद्र यादव ने किया। राष्ट्रीय सद्भावना पुरुस्कार से सम्मानित विनोबा विचार प्रवाह के संत श्री रमेश भइया ने भी गांधी विनोबा के विचारों का।उल्लेख इस अवसर पर किया।

प्रतियोगिता बच्चों के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त माध्यम होती – जी डी शुक्ला

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बीव आरव पीव इन्टर कॉलेज में वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को कॉलेज के पूर्व प्राचार्य स्वव कृपाशंकर श्रीवास्तव स्मृति जनपदस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जीव डीव शुक्ला जी ने प्रतियोगिता के विषय "आत्मनिर्भर भारत" के बारे में बच्चों से अपने विचार साझा किए और कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता बच्चों के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त माध्यम होती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रविकांत जायसवाल जी, कलाविद रहे। उन्होंने बच्चों को चित्रकला की बारीकियों के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रवींद्र अस्थाना जी ने की। कार्यक्रम में श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव (प्रबंधक), बीव आरव पीव इन्टर कॉलेज, ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर हुए अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिलीप श्रीवास्तव, (प्रबंधक) मुक्तेश्वर प्रसाद बालिका इन्टर कॉलेज, अंशु श्रीवास्तव एवं राजन श्रीवास्तव दीपक श्रीवास्तव पत्रकार उपस्थित रहे। विद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य डॉ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सबका सम्मान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ ऋषि श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में पंचलाल राम, प्रकाश यादव, सोम वर्मा, सत्य प्रकाश सरोज, शुभम तिवारी, श्रीमती सीमा राज, श्रीमती शिवानी तिवारी, आदि अध्यापक उपस्थित रहे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी दीपक श्रीवास्तव ने दिया।

विधायक प्रतिनिधि पर हमला करने वाले तीन हमलावरो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक डा0 अजय पाल शर्मा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर अरबिन्द कुमार वर्मा के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रामाश्रय राय के नेतृत्व में थाना खेतासराय पुलिस टीम द्वारा विधायक प्रतिनिधि पर हमला करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। 22 नवंबर को विधायक प्रतिनिधि खुर्शीद अनवर पुत्र फैय्याज अहमद निवासी पाराकमाल थाना खेतासराय जौनपर के उपर 4–5 अज्ञात बदमाशो द्वारा लाठी डण्डा व राड से हमला कर घायल कर दिया था जिसपर खुर्शीद अनवर के पिता फैय्याज अहमद की

तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा बीएनएस बनाम 4–5 अज्ञात पंजीकृत किया गया था। इलेक्ट्रानिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल हमलावरों को आजाद नहर पुलिया से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में

1–अंकित मौर्य पुत्र राजेन्द्र मौर्य गोपालापुर थाना कोतवाली जौनपुर।

2–दीपक जायसवाल पुत्र राजकुमार जायसवाल निवासी सकरमण्डी थाना कोतवाली जौनपुर।

3–अंकुल मौर्य पुत्र सुदर्शन मौर्य निवासी पदुमपुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन परिसर में एसबीआई एटीएम का किया उद्घाटन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा राजभवन परिसर में एसबीआई एटीएम का उद्घाटन एसबीआई लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक शरद स. चांडक की उपस्थिति में किया गया। महामहिम ने एसबीआई की इस पहल को पूर्ण डिजिटल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और साथ ही सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एटीएम का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, डॉ. सुधीर एम. बोबड़े, राजभवन के अन्य अधिकारीगण, एसबीआई के महाप्रबंधक अनिल कुमार, नेटवर्क–1 और कौशलेन्द्र कुमार, नेटवर्क–3 के साथ बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जीवन में किताबों के मोल को समझने वाला होता है सफल – प्रो. वंदना सिंह

पढ़े विश्वविद्यालय– बढ़ें विश्वविद्यालय कार्यक्रम का हुआ आयोजन

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राजभवन लखनऊ के दिशा निर्देश के क्रम में गुरुवार को पढ़े विश्वविद्यालय– बढ़ें विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय में विद्यार्थियों के साथ किताब पढ़ी।

कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किताबें हमेशा से हमारे साथ ही रही है और हमेशा साथ रहेंगीं. जीवन में जिसने किताबों के मोल को समझा वो निश्चित रूप से सफल होता है. किताबें हमारे जीवन में सबसे बड़े पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करतीं है. किताबें ज्ञान का भंडार है हमें किसी भी विषय पर अगर कोई भी ज्ञान चाहिए तो किताबें उसे प्रदान करतीं है. आज के दौर में ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने के लिए उपलब्ध है, लेकिन ऑफलाइन पुस्तकें पढ़ने की आदत होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए किताबों की बड़ी महत्ता है. शिक्षक पुस्तकों को आधार बना कर ही विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि किताबों से कभी दूर मत हो

व्यवहारिक मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि किताबों को पढ़ने से हमारी सोच में बदलाव आता है. अपने विषय के साथ ही साथ प्रेरणादायक पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं प्रबंधा अध्ययन संकाय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने अपने–अपने विभाग में पुस्तक पढ़ीं. वहीं इसके साथ ही प्रशासनिक भवन में विश्वविद्यालय के कुलसचिव महेंद्र कुमार, परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी किताबें पढ़ीं। परिसर के विभिन्न संकायों में आयोजित कार्यक्रम में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अजय द्विवेदी, प्रो. मानस पाण्डेय, प्रो. राजेश शर्मा, प्रो. सौरभ पाल, प्रो. प्रमोद यादव, प्रो. अशोक श्रीवास्तव, प्रो. रजनीश भास्कर, प्रो. राज कुमार, प्रो. देवराज, प्रो. गिरिधिर मिश्र, डॉ. एसपी तिवारी, डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ. वनिता सिंह समेत विभिन्न संकायों में शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारियों ने पुस्तक पढ़ीं।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट का एक दिवसीय धरना,10 शिक्षकों की मांगे ?

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। 27–11–24 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट का एक दिवसीय धरना ईको गार्डन लखनऊ के प्रांगण में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सीताराम यादव जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री बाल बिहारी यादव जी सदस्य विधान परिषद शिक्षण खण्ड– वाराणसी नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद शासन लखनऊ तथा विशिष्ट अतिथि श्री आशुतोष सिन्हा जी सदस्य विधान परिषद स्नातक क्षेत्र वाराणसी उपस्थित रहे। माननीय लाल बिहारी जी ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को मनेरगा मजदूर के बराबर भी वेतन नहीं मिल रहा। शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय के लिए शिक्षको की एक जुट होना होगा। आशुतोष सिन्हा जी ने भी वित्तविहीन शिक्षकों की मांग को सरकार से मनवाने के लिए बाध्य करने का कार्य करेंगे।

नैट परीक्षा में 123452 बच्चों के सापेक्ष 121232 बच्चें परीक्षा में हुए शामिल – बीएसए

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की निपुण एसेसमेण्ट टेस्ट (नैट) परीक्षा के दृष्टिगत बीएसए ने स्कूलों का किया निरीक्षण, अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्यवाही, 98 प्रतिशत बच्चों ने परीक्षा दी शुचितापूर्ण सम्पन्न।

जनपद जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित परिषदीय प्राथमिकध्उच्च प्राथमिकध्कम्पोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की निपुण एसेसमेण्ट टेस्ट (नैट) परीक्षा 27 नवम्बर, 2024 को आयोजित की गयी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 गोरखनाथ पटेल ने बताया कि जनपद में निपुण एसेसमेण्ट टेस्ट (नैट) परीक्षा, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालयों में कक्षा 01 से 03 में अध्ययनरत 123452 बच्चों के सापेक्ष 121232 बच्चें परीक्षा में सम्मिलित हुए।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनपुस्थित मिले शिक्षक, शिक्षामित्रों को बीएसए द्वारा वेतन एवं मानदेय अवरुद्ध करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

बुधवार को बीएसए ने परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक नकलविहीन शुचितापूर्ण ढ़ग से नैट परीक्षा करवाने हेतु छात्र अध्यापक उपस्थिति का अनुश्रवण करने के उद्देश्य से विकासखांड मड़ियाहूं, महराजगंज एवं सुजानगंज में अवस्थित विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया।

बीएसए ने बुधवार को सर्वप्रथम सुबह 09:25 बजे दूरभाष के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रही शिकायत के क्रम में विकास खण्ड मड़ियाहूँ के कम्पोजिट विद्यालय बहरैचा का औचक निरीक्षण समय 09:25 बजे किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक विनोद कुमार सिंह, अंकित जायसवाल, शिक्षामित्र श्रीमती आशा देवी एवं अनीता यादव अनुपस्थित पाये गये है, शेष अन्य कार्यरत अध्यापक उपस्थित पाये गये।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल नामांकित 148 छात्रों के सापेक्ष 108 छात्र विद्यालय में उपस्थित मिले। सहायक अध्यापक विनोद कुमार सिंह, अंकित जायसवाल, संतोष कुमार सिंह शिक्षामित्र श्रीमती आशा देवी एवं अनीता यादव को निपुण एसेसमण्ट टेस्ट जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यदिवसों में अनुपस्थिति के कारण दिनांक 27 नवम्बर 2024 का वेतनध्मानदेय अवरुद्ध करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया।

विकास खण्ड मड़ियाहूँ के प्राथमिक विद्यालय कुठुली के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल नामांकित 62 छात्रों के सापेक्ष 55 छात्र विद्यालय में उपस्थित मिले। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान निपुण एसेसमण्ट टेस्ट शुचितापूर्वक होती पायी गयी।

विकास खण्ड सिकरारा के प्राथमिक विद्यालय बिसावॉ के निरीक्षण के दौरान निपुण एसेसमण्ट टेस्ट शुचितापूर्वक होती पायी गयी।

विकास खण्ड सुजानगंज के प्राथमिक विद्यालय बेलावॉ के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत कमलेश कुमार प्रा0वि0 कुरौवॉ पर्यवेक्षक के रुप में गये हुए तथा समस्त कार्मिक उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल नामांकित 99 छात्रों के सापेक्ष 90 छात्र विद्यालय में उपस्थित मिले। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान निपुण एसेसमण्ट टेस्ट शुचितापूर्वक होती पायी गयी। एमडीएम खाकर चेक किया गया!

विकास खण्ड महराजगंज के प्राथमिक विद्यालय चेती के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल नामांकित 112 छात्रों के सापेक्ष 110 छात्र विद्यालय में उपस्थित मिले। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान निपुण एसेसमण्ट टेस्ट शुचितापूर्वक होती पायी गयी।

विकास खण्ड महराजगंज के प्राथमिक विद्यालय चरियारी द्वितीय एवं प्राथमिक विद्यालय चरियारी प्रथम का औचक निरीक्षण समय 02:15 बजे किया गया। दोनों विद्यालयों में में निरीक्षण के दौरान निपुण एसेसमण्ट टेस्ट शुचितापूर्वक होती पायी गयी। प्राथमिक विद्यालय चरियारी प्रथम में शौचालय गन्दा पाये जाने के कारण प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नाटिस जारी कर दिया गया।

अधूरे पुलों के पहुंच मार्ग पर बनेगी 1.5 मीटर ऊंची दीवार, बरेली हादसे के बाद शासन ने लिया फैसला

लखनऊ,(संवाददाता)। अधूरे और क्षतिग्रस्त पुलों के पहुंच मार्ग पर डेढ़ मीटर ऊंची आरसीसी की दीवार बनाई जाएगी। बरेली में हुए हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि असुरक्षित, क्षतिग्रस्त और अधूरे पुलों पर वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए तीन दीवारें निर्मित होंगी। पहली दीवार संवेदनशील स्थल से 20–25 मीटर दूरी पर, दूसरी दीवार 50–100 मीटर की दूरी पर और तीसरी एप्रोच रोड पर दोनों ओर बनाई जाएगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सेतुओं का सहायक अभियंता सप्ताह में एक बार, अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता 15 दिन में एक बार और मुख्य अभियंता महीने में एक बार निरीक्षण करेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में अगले साल आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले को अच्छे से संपन्न कराने के लिए 25 पीसीएस अधिकारी और 16 और नायब तहसीलदारों की तैनाती की है। नियुक्ति और राजस्व परिषद की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। महाकुंभ के लिए बनाए जाने वाले सेक्टरों का प्रभारी पीसीएस अधिकारियों को बनाया गया है और उनके साथ तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को लगाया गया है।

कर्ज में डूबे युवक ने 11 साल के बच्चे को अगवा कर पांच लाख की फिरौती मांगी, नहीं दी तो कर दी हत्या

लखनऊ,(संवाददाता)। सुल्तानपुर में कर्ज में डूबे युवक ने 11 वर्षीय छात्र को अगवा कर 5 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं मिलने पर मासूम की हत्या कर दी। 36 घंटे तक पीड़ित परिजन पुलिस से मदद मांगते रहे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नगर कोतवाली के गांधीनगर मोहल्ले में बुधवार सुबह मासूम की हत्या की खबर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात शाहगंज चौकी से चंद कदम दूरी पर हुई। मासूम चौथी कक्षा का छात्र था। मामले की जानकारी पर

देहात कोतवाल सत्येंद्र सिंह, धम्मौर थाना अध्यक्ष ज्ञानचंद्र, कुड़वार थाना अध्यक्ष चंद्रभान वर्मा, नगर कोतवाल नारद मुनि मौके पर पहुंचे। सुबह हुई सनसनीखेज वारदात से जिले में हड़कंप मच गया है। एसपी सोमेन बर्मा बोले हत्यारोपी युवक लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ था। हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांधीनगर के मोहम्मद शकील का बेटा उसामा (11) 25 नवंबर की रात आठ बजे घर से बरात देखने निकला था। उसामा चौथी कक्षा का छात्र था। मंगलवार को उसके पिता ने शहर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। हत्यारोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शहर के राहुल चौराहे के पास छात्र की हत्या की गई और बुधवार सुबह पुलिस ने शव बरामद कर लिया।

जांच कमेटी ने शासन को भेजी रिपोर्ट, कई स्तर पर मिली हैं खामियां

लखनऊ,(संवाददाता)। प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों की अग्नि सुरक्षा को लेकर नए सिरे से ऑडिट शुरू कर दी गई है। पूर्व में हुए ऑडिट में बताई गई खामियों को चिह्नित करते हुए अन्य जरूरी बिंदुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। सभी संस्थानों के निदेशकों और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को चेक लिस्ट भेजी गई है। चेतावनी दी गई है कि संबंधित खामियां दूर नहीं हुई और भविष्य में किसी तरह की घटना हुई तो वे खुद जिम्मेदार होंगे। झांसी अग्निकांड के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नए सिरे से सभी चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों की फायर व सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। इसके तहत चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से अग्नि सुरक्षा विभाग और बिजली विभाग की ओर से की गई ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इसमें चिह्नित की गई खामियों और सुरक्षा से जुड़े अन्य बिंदुओं को जोड़ते हुए नए सिरे से चेक लिस्ट तैयार की गई है। इसमें अग्नि सुरक्षा बचाव के एहतियात के तौर पर सभी बिंदुओं को समाहित कर जवाब मांगा गया है। संस्थान के निदेशकों एवं कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को चेक लिस्ट भेजते हुए चेतावनी भी दी गई है।

प्रदेश में पान मसाला उत्पादन हुआ ठप, इकाइयों के बाहर 60 से ज्यादा टीमें तैनात

लखनऊ,(संवाददाता)। प्रदेश में पान मसाला इंडस्ट्री पर शासन का कहर टूट पड़ा है। लखनऊ, कानपुर सहित अन्य जिलों में बनने वाले पान मसाला इकाइयों के बाहर 24 घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगाने का आदेश प्रमुख सचिव एम देवराज ने जारी कर दिया है। अकेले लखनऊ और कानपुर में 54 टीमें केवल पान मसाला की निगरानी कर रही हैं। इससे एक तरफ पान मसाले का उत्पादन पूरी तरह ठप होने के कगार पर पहुंच गया है तो दूसरी तरफ प्रदेश में नकली और टैक्स चोरी से आने वाले मसाले की बाढ़ आ गई है। सड़क पर जांच प्रभावित होने से 20 करोड़ रुपए रोज का टैक्स चोरी का माल दूसरे राज्यों से आने लगा है। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, हरदोई,गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, हापुड़, कानपुर देहात, उन्नाव, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, खलीलाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर में पान मसाला इकाइयां हैं। शासन ने पान मसाला इकाइयों से निकलने वाले वाहनों की अनिवार्य ई वे बिल स्कैनिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पान मसाला ब्रांड की फैक्टरी के बाहर 12–12 घंटे के रोस्टर में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी के दौरान बॉडीवार्न कैमरा पहनना अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया है कि एक मिनट के लिए भी टीम जगह नहीं छोड़ेगी। दूसरी टीम आने के बाद ही पहली टीम हटेगी। चेतावनी दी गई है कि एक भी वाहन बिना ई वे बिल की स्कैनिंग के पाया गया तो अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। अभी 30 नवंबर तक इस रोस्टर को लागू किया गया है। ये भी कहा गया है कि व्यापारियों के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आएं। गलत व्यवहार न किया जाए और माल की आवाजाही न रोकी जाए। इस सख्ती की वजह से पान मसाला इकाइयों में उत्पादन लगभग बंद हो गया है। जांच के दायरे में प्रमुख रूप से पुकार, शिमला, गोमती, कमला पसंद, कायम, दबंग, हरश्रंगार, शिखर, केसर, सिग्नेचर, एसएनके, शुद्ध प्लस, तिरंगा और किसान पान मसाला ब्रांड आए हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक करीब पांच उद्यमी यूपी की सीमा से लगे राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली और गुड़गांव में इकाई लगाने की तैयारी में हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अधिकांश टीमों की चौबीस घंटे ड्यूटी मसाला इकाइयों के बाहर लगते ही नकली पान मसाला की आवक तीन गुना तक बढ़ गई है। चूंकि नकली मसाला फैक्टरी से राजस्व नहीं मिलता इसलिए अधिकारियों की उन्हें पकड़ने में खास रुचि नहीं होती। राज्य कर विभाग की जांच से सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी राजस्व को लेकर परेशान हो गए हैं। दरअसल पान मसाला पर 28 फीसदी जीएसटी और 60 फीसदी सेस है। सेस पूरी तरह सेंट्रल जीएसटी को मिलता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक का लखनऊ दौरा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक कबीर भट् टाचार्य एवं प्रवीण शर्मा ने लखनऊ अंचल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय से आये शाखा प्रमुखों से बैंक के द्वारा दिये गये विभिन्न कारोबार लक्ष्यों जैसे जमा धनराशि, ऋण स्वीकृत, ऋण वसूली इत्यादि एवं भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की। इसके

अतिरिक्त यूनियन बैंक भवन के सभागार में उन्होने लखनऊ अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालय के सभी यूनियन बैंक स्टाफ सदस्यो को सम्बोधित किया एवं बैंक के विजन तथा विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, साथ ही बैंकिंग सेवाएं त्वरित रूप से ग्राहकों तक पहुँचाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। मुख्य महाप्रबंधक कबीर भट् टाचार्य एवं प्रवीण शर्मा ने पौधा रोपण भी किया तथा पर्यावरण की महत्वता पर विशेष प्रकाश डालते हुए सभी को अपने आस–पास के सार्वजनिक आवश्यक स्थानो पर पौधा रोपण हेतु निर्देशित किया। मौके पे उपस्थित अंचल प्रमुख राजेश कुमार ने पौधा रोपण हेतु स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित किया।

यूपी के मंत्री बोले– इजराइल में बढ़ रही कुशल युवाओं की मांग, यहां के युवा बनाएंगे नया इजराइल

लखनऊ,(संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के युवा खेती, उद्योग से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में नए कौशल सीख रहे हैं। वर्तमान में इजराइल में कुशल भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। भारत–इजराइल ड्राइव 3.0 में 5 हजार लोगों को इजराइल भेजा जाएगा। नया इजरायल कुशल भारतीय युवा पीढ़ी के हाथों बनेगा। बुधवार को यूपी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भारत–इजराइल ड्राइव 3.0 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को इजराइल में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान और बेहतर भविष्य का मार्ग मिल रहा है। इजराइल सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत अब तक 9,000 से अधिक श्रमिकों को इजराइल में रोजगार मिल चुका है। इन श्रमिकों को भवन निर्माण, मॉल प्रबंधन और तकनीकी कार्यों में काम करने के अवसर दिए जा रहे हैं, जहां उन्हें 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। श्रमिकों की भाषा एवं कौशल दक्षता को सुधारने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उन्हें कार्यस्थल पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। युवाओं को डिमांड आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें ऐसे क्षेत्रों में तैयार किया जा रहा है जहां उनकी सक्षमता और हुनर का बेहतर उपयोग हो सके। यह पहल केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल से अनुभव प्राप्त कर लौटने वाले श्रमिक नए रोजगार सृजन और अपने व्यवसाय को और अधिक उन्नत करने में भी सक्षम हो रहे हैं। योगी सरकार का यह अभूतपूर्व कदम राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

लंबित आडिट आपत्तियों की शीघ्र करें निस्तारण – अपर आयुक्त प्रशाशन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। अपर आयुक्त प्रशासन वाराणसी मंडल श्री राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर आयुक्त ने सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार से वसूली संबंधी आपत्तियां, अभिलेखों के निर्माण, वित्तीय अनियमितता, अप्रस्तुत, अभिलेख, दैवीय आपदा, कृषक दुर्घटना बीमा योजना भूलेख आदि के संदर्भ में लंबित आडिट आपत्तियों के

निस्तारण की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया की आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र करना सुनिश्चित करें साथ ही उन्होंने भूराजस्व की मांग, अंश निर्धारण की प्रक्रिया आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां भी अंश निर्धारण होना है वहां इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही इसकी प्रगति की समीक्षा सभी तहसीलदार नियमित रूप से करते रहें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामअक्षयवर चौहान,ज्वांइट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह सहित उपजिलाधिकारीगण, तहसीलदारगण सहित अन्य उपस्थित रहे।

प्रदेश में कल से होगी कोहरे की वापसी, 20 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

लखनऊ,(संवाददाता)। प्रदेश में बुधवार से मौसम दोबारा करवट लेगा। तराई इलाकों में कोहरे का घनापन बढ़ने के साथ ही पश्चिमी यूपी समेत अन्य इलाकों में भी कोहरे का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए 20 से ज्यादा इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी किया है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन में पछुआ हवाएं चलीं और धूप खिली रही। शाम को हवा में ठिठुरन महसूस हुई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि बुधवार से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धीरे–धीरे दिने के तापमान में हल्की गिरावट आएगी। वहीं अगले कुछ दिनों में रात के पारे में भी क्रमशरू 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। मंगलवार को उरई में सर्वाधिक 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं वाराणसी में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री और प्रयागराज में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो बुलंदशहर में 10 डिग्री, मुरादाबाद में 10.4 डिग्री और नजीबाबाद में 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के तराई इलाकों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर समेत देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, , गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी किया है।

बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद रौंदते हुए निकल गई बस, बाल–बाल बचा बच्चा

लखनऊ,(संवाददाता)। कोतवाली महोली क्षेत्र के उरदौली कस्बे के पास बुधवार दोपहर एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद बस बाइक सवार महिला व पुरूष को रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में एक दो वर्षीय मासूम सुरक्षित बच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं, बस व चालक को हिरासत में ले लिया है। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था। इलाके के उरदौली कस्बा क्षेत्र के नेशनल हाइवे पर एक कैसरबाग डिपो की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला व पुरूष छिटककर सड़क पर गिरे, उनके सिर के ऊपर से बस का पहिया रौंदते हुए निकल गया। वहीं, बच्चा (2) बायीं ओर गिरा जिससे वह सुरक्षित रहा। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है।

पैसा लेकर ट्रक छोड़ने के आरोप में राज्य कर में सहायक आयुक्त सहित दो सस्पेंड, विभाग में खलबली

लखनऊ,(संवाददाता)। राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी को पैसा लेकर ट्रक छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त अपूर्वा पटेल और राज्य कर अधिकारी नरेश कुमार मेरठ सचल दल में तैनात हैं। दोनों के निलंबन का आदेश प्रमुख सचिव एम. देवराज ने मंगलवार देर शाम जारी कर दिया। ताजा कार्रवाई के बाद पहले से ही विभाग में मची खलबली और तेज हो गई है। शासनादेश के मुताबिक दसन एंड मून कंपनी का माल लदा ट्रक हरियाणा से हल्द्वानी जा रहा था। 25 अक्तूबर को ट्रक रोककर मेरठ सचल दल इकाई तृतीय की सहायक आयुक्त अपूर्वा पटेल और राज्य कर अधिकारी नरेश अग्रवाल ने जांच की थी। बताया जाता है कि ट्रक में गिफ्ट आइटम थे। इस मामले में पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने की शिकायत हुई थी, जिसके जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में शिकायत प्रथमदृष्टया सही पाई गई, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। दोनों अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद पूरे प्रकरण की जांच के लिए विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। निलंबन की अवधि तक दोनों अधिकारी अपर आयुक्त ग्रेड–1 झांसी से संबद्ध रहेंगे। इससे पहले 11 वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। ये कार्रवाईयां आदेशों का अनुपालन न करने और राजस्व वृद्धि का टारगेट पूरा न करने की वजह से की गई थी।

रामदरबार के पूरा होने की तारीख तय, रामलला को अब तक उपहार में मिली 940 किलो चांदी

लखनऊ,(संवाददाता)। राममंदिर के दूसरे तल पर स्थापित होने वाले रामदरबार की मूर्तियां 15 जनवरी तक बनकर अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन मूर्तियों का निर्माण राजस्थान के जयपुर में हो रहा है। इसके अलावा सप्तमंडपम के सात मंदिरों की सात मूर्तियां व परकोटे के छह मंदिरों की छह मूर्तियां भी जयपुर में ही बन रही हैं। ये सभी मूर्तियां जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएंगी। राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम दरबार की मूर्ति का परीक्षण आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा पूरा कर चुके हैं, मूर्तियां संतोषजनक पाई गई हैं। संगमरमर के पत्थर पर मूर्तियों को आकार देने का काम चल रहा है। विख्यात शिल्पकार वासुदेव कामत राम दरबार को आकार दे रहे हैं। राम दरबार में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुहन व हनुमान की मूर्तियां एक साथ रहेंगी। यह मूर्ति 15 जनवरी तक बनकर अयोध्या पहुंच जाएगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राममंदिर के 800 मीटर लंबे परकोटे में कांस्य के 90 भित्तिचित्र बनाए जा रहे हैं। इनमें से 11 म्यूरल यानी भित्ति चित्र बनकर तैयार हो चुके हैं। एक म्यूरल की लंबाई सात फीट व चौड़ाई छह फीट है। इनके निर्माण में पांच शिल्पकार लगे हुए हैं। परकोटे का संपूर्ण काम अक्तूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राममंदिर में चार प्रवेश द्वार बनने हैं, जिसका डिजाइन तैयार है। राजकीय निर्माण निगम ये द्वार बना रहा है। उत्तरी गेट पर कार्य शुरू हो चुका है। 11 नंबर गेट का भी कार्य जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है, उसके बाद गेट नंबर तीन और गेट नंबर 10 भी बनाए जाएंगे। जून 2025 तक चारों प्रवेश द्वार बनकर तैयार हो जाएंगे। ये प्रवेश द्वार भी वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से बनाए जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक संयुक्त

संदिग्ध हालात में फंदे से लटकी मिली विवाहिता, मायके वालों ने लगाया आरोप– हत्या हुई

लखनऊ,(संवाददाता)। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालात में फंदे पर लटका मिला है। मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर मेहमानपुर गांव निवासी राम मनोहर मिश्र के बेटे रोहित की शादी बाराबंकी जिले के सुबेह थाना क्षेत्र स्थित अहीर से महिमा के साथ 4 मार्च को हुई थी। मंगलवार सुबह महिमा कमरे के अंदर संदिग्ध हालात में फंदे से लटकी मिली। घटना के समय मृतका का पति ट्रैक्टर लेकर खेत गया था जबकि परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद थे। घटना की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया।

ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब, हाईकोर्ट में सुनवाई

लखनऊ,(संवाददाता)। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के समक्ष एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। राज्य सरकार के मुख्य

स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। वहीं, याची ने भी इसका प्रतिउत्तर दाखिल कर दिया है। हालांकि, मामले में कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। फिलहाल ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में 27 नवंबर तक महाराजगंज बाजार के कथित अतिक्रमणकर्ताओं को राहत रहेगी। पहले, कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा था कि क्या नोटिसें जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था या नहीं? क्या जिन्हें नोटिसें जारी हुईं, वेलोग निर्मित परिसरों के स्वामी हैं या नहीं? नोटिस जारीकर्ता प्राधिकारी इन्हें जारी करने को सक्षम था या नहीं। इन बिंदुओं के अलावा कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि महराजगंज बाजार की जिस सड़क पर बने निर्माणों को ढहाने की नोटिस जारी हुईं, क्या पूरा निर्माण या उसका कोई हिस्सा अवैध निर्माण था या नहीं? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की थी कि फिलहाल राज्य सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे, जो कानून सम्मत न हो। याचिका में बहराइच के महाराजगंज बाजार के कथित अतिक्रमणकर्ताओं को बीते 17 अक्तूबर को जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देकर इन्हें रद्द करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

सदन में बढ़ रहे पीएचडी, प्रबंधन व डॉक्टर डिग्रीधारक विधायक

लखनऊ,(संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से एपी सेन सभागार में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि राजनीति में अच्छे, सच्चे और युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विधानसभा में अच्छी संख्या में डॉक्टर, प्रबंधन और पीएचडी की उपाधिधारक विधायक चुनकर आ रहे हैं। उन्होंने संविधान दिवस पर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए राजनीतिक व्यवस्था और उसके पदाधिकारियों के प्रति अधिक सकारात्मक और आशावादी रवैया अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कुलपति प्रो. आलोक राय, प्रति कुलपति प्रो. मनुका खन्ना, विभागाध्यक्ष प्रो. संजय गुप्ता, प्रो. वीके शर्मा, प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव व सभागार में मौजूद सभी लोगों को संविधान के अनुपालन की शपथ दिलाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विवि के विधि विभाग में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान भारतीय संस्कृति से जुड़े दर्शन की व्याख्या करता है जहां विश्व को वसुधैव कुटुंबकम् के सूत्र में पिरोने का संदेश हमारे राष्ट्र ने दिया है। कार्यक्रम में लोहिया विधि विवि के कुलपति प्रो. अमरपाल सिंह, लविवि की प्रो. विनीता काचर, केंद्रीय संचार ब्यूरो के निदेशक मनोज वर्मा व विभागाध्यक्ष प्रो. सुदर्शन वर्मा आदि मौजूद रहे। भाषा विवि में कुलपति प्रो. एनबी सिंह ने सभी शिक्षकों की मौजूदगी में संविधान की प्रस्तावना दोहराई और शपथ दिलवाई। इस मौके पर कई प्रतियोगिताएं भी हुई। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि के विधि संकाय में संविधान सप्ताह का समापन हुआ। अधिष्ठाता प्रो. शेफाली यादव ने प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कृत किया। जयनारायण मिश्र महाविद्यालय में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि लविवि के प्रो. राकेश मिश्र ने संविधान निर्माण व उसके वर्तमान संदर्भों पर बात की। प्राचार्य प्रो. विनोद चंद्रा व विद्यार्थी मौजूद रहे। शिया पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना की प्रतियां बांटी गईं। मुख्य वक्ता डॉ. रॉबिन वर्मा ने कहा कि संविधान ही भारत के लोगों का असल ग्रंथ है। प्राचार्य प्रो. एसएस बाकरी, प्रो. जर्रीन जेहरा रिजवी, डॉ. प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। अटल बिहारी बाजपेई नगर निगम डिग्री कॉलेज में प्राचार्य प्रो. सुभाष चंद्र पांडेय ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान को नमन किया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।